

एशिया का उदय - वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए निहितार्थ *

या.वे. रेड्डी

बैंक ऑफ मारीशस के 40वें वार्षिक समारोह के अवसर पर स्मारक भाषण देने के लिए आमंत्रित किया जाना एक गौरव की बात है। यह निमंत्रण न केवल भारत और मारीशस के बीच बल्कि दो केंद्रीय बैंकों के बीच घनिष्ठ संबंधों को दर्शाता है, दोनों केंद्रीय बैंकों के बीच पारस्परिक लाभपूर्ण और बहुत घनिष्ठ संबंध हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से गवर्नर भीनिक के प्रति आभारी हूँ जो उन्होंने मुझे यहाँ आने का अवसर दिया।

माननीय प्रधान मंत्री, डा. नवीनचंद्र रामगुलाम ने 24 अगस्त 2007 को अपने संबोधन में, बैंक ऑफ मारीशस के 40 वें वार्षिक समारोह के अवसर पर बैंक की भूरि-भूरि प्रशंसा की। उन्होंने विशेष रूप से उस प्रयास और समर्पण का जिक्र किया जिसके कारण बैंक "एक सफल और सम्मानित संस्था" बन सका। मैं आगे कहना चाहूँगा कि बैंक वैश्विक तौर पर एक सम्मानित संस्था बन गया है और हमें, रिजर्व बैंक को मारीशस में अपनी सहयोगी संस्था में पूरा भरोसा और विश्वास है।

अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक, बासेल, स्विटजरलैण्ड ने 99/2007 की अपनी समीक्षा में 24 अगस्त 2007 को इसी अवसर पर गवर्नर भीनिक के संबोधन को प्रकाशित किया जिसका शीर्षक है "इस्केपिंग दि फेट ऑफ डोडो"। इसमें बैंक ऑफ मारीशस के न केवल विकास और बदली हुई परिस्थितियों के प्रति सफलतापूर्वक अनुकूलन बल्कि केंद्रीय बैंकिंग के सिद्धांत और व्यवहारों को प्रस्तुत किया गया है। आगामी कार्यों के संबंध में, गवर्नर भीनिक ने कहा कि "इस केंद्रीय बैंक को बैंक ऑफ मारीशस से बैंक ऑफ मारीशस, जनता

* 3 दिसंबर 2007 को मारीशस में बैंक ऑफ मारीशस के 40वें वार्षिक समारोह के अवसर पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर डॉ. या. वे. रेड्डी द्वारा दिया गया स्मारक भाषण।

के बैंक के रूप में परिवर्तित होने की आवश्यकता है। हमें हरेक परिवार के लिए सुदृढ़ वित्तीय विकल्प बनाने होंगे, आसान विकल्प"। हम, भारतीय रिज़र्व बैंक ने हाल ही में ऐसे ही अधिदेश तय किए हैं। मैं औपचारिक रूप से बैंक ऑफ मारीशस को इसके 41वें वर्ष की सफल यात्रा के लिए बधाई देना चाहता हूँ और वृद्धि, स्थायित्व तथा सबसे ऊपर, आम आदमी की सेवा के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए शुभ कामनाएं देता हूँ।

आज के भाषण का विषय है "एशिया का उदय : वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए निहितार्थ"। मैं इस विषय को बड़ी विनम्रता के साथ प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मेरी मारीशस की पहली यात्रा 1997 में राष्ट्रकुल वित्त मंत्रियों के सम्मेलन के संबंध में हुई थी। यहाँ से, मुझे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष/विश्व बैंक के वार्षिक सम्मेलन में भाग लेने के लिए हांग कांग पहुँचना था। लेकिन, मैंने हांग कांग की अपनी यात्रा रद्द करना उचित समझा और उसके स्थान पर मुंबई वापस चला गया क्योंकि भारत के वित्तीय बाजार में कुछ घबराहट के संकेत मिले थे। यह वह समय था जब एशियन संकट अपने पूर्ण स्वरूप में था। महीनों और वर्षों के पश्चात, हमने एशियन अर्थव्यवस्था की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं और परिणामी कठिनाइयों तथा सुधारों की आवश्यकता पर विचार विमर्श किया। दस वर्ष के पश्चात, मारीशस की अपनी दूसरी यात्रा में, अब हम न केवल एशियाई अर्थव्यवस्थाओं की सफलता का जश्न मना रहे हैं बल्कि इस पर भी विचार कर रहे हैं कि कैसे वे वैश्विक वृद्धि और स्थायित्व में योगदान कर सकती हैं। एशियन क्षेत्र के लिए यह एक विलक्षण दौर रहा है और कोई भी दस अथवा पाँच वर्ष पहले इस परिणाम की भविष्यवाणी नहीं कर सकता था।

दूसरे, क्या कोई वित्तीय बाजार में ऐसे उथल-पुथल की प्रत्याशा कर सकता था जो संयुक्त राज्य अमरीका जैसी उन्नत अर्थव्यवस्थाओं तथा विशेष रूप से वैश्विक वित्तीय केंद्र से उत्पन्न होगा ?

तीसरे, कितने लोग ऐसी स्थिति की कल्पना कर सकते थे कि कैसे सबसे बड़े वित्तीय मध्यस्थ, विशेष रूप से वैश्विक बैंक, जिनको जोखिम प्रबंधन क्षमताओं के लिए काफी अधिक ऊँचे स्थान पर रखा जाता है, अचानक एक दूसरे की चलनिधि स्थिति में पूरा भरोसा खो देंगे और एक दूसरे के प्रति व्यवहार करने में अनिच्छुक हो जाएंगे। फलस्वरूप, कुछ केंद्रीय बैंकों ने, शायद उचित रूप में, असाधारण उदारता के साथ प्रणाली में काफी अधिक चलनिधि डाली।

चौथे, एक संबंधित घटना में, एक प्रमुख वैश्विक वित्तीय केंद्र में सरकार को एक ऐसे बैंक की सहायता के लिए कदम उठाने पड़े जिस बैंक से भारी मात्रा में आकस्मिक आहरण किए जाने लगे थे - ऐसा दृष्टिकोण जिस पर हाल के वर्षों में सरकार द्वारा शायद ही कभी ध्यान दिया गया।

संक्षेप में, विनम्रता के साथ इस आवश्यकता की ओर ध्यान दिलाना चाहूँगा क्योंकि हाल के इतिहास से पता चलता है कि हमारे पास देशों के आर्थिक दृष्टिकोण के लिए अथवा वैश्विक अर्थव्यवस्था के संबंध में निश्चितता के साथ भविष्यवाणी करने के लिए पर्याप्त ज्ञान नहीं है। फिर भी, वर्तमान वैश्विक आर्थिक वातावरण विशेष रूप से अनिश्चित है, जो ऐसे भविष्यात्मक अभ्यास को बहुत प्रायोगिक बना देता है।

इस पृष्ठभूमि में, मैं वैश्विक संदर्भ में एशियन अर्थव्यवस्थाओं के बारे में कुछ धारणाओं को प्रस्तुत

करना चाहता हूँ। प्रारंभ में, हमें मानना होगा कि एशिया एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसमें अनेक देश और विभिन्न आकार तथा स्वरूप की अर्थव्यवस्थाएँ हैं, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था और एक दूसरे के साथ भी एकीकृत होने की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। इसलिए यहाँ जो भी कहा गया है, अति व्यापक सामान्यीकरण है।

वैश्विक अर्थव्यवस्था में एशिया के बढ़ते महत्व के लिए पर्याप्त दस्तावेज हैं और इसलिए संक्षेप में उल्लेख पर्याप्त होगा। एशिया विश्व की दस सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से तीन पर गर्व कर सकता है - जापान, चीन और भारत। 1980 में, एशिया में, क्रय शक्ति समता के अनुसार वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का हिस्सा 19 प्रतिशत था। आज, एशिया का हिस्सा 36 प्रतिशत के ऊपर है और वर्ष 2020 तक इसके 45 प्रतिशत से अधिक होने की आशा है। वर्तमान में, क्रय-शक्ति समता के अनुसार एशिया का हिस्सा विश्व वृद्धि के 50 प्रतिशत के करीब है। वैश्विक व्यापार में एशिया का हिस्सा तेजी से बढ़ रहा है और एशिया के अंतर्गत व्यापार भी आकर्षक तरीके से बढ़ रहा है। एशियन अर्थव्यवस्थाएँ पहले की अपेक्षा अब एक दूसरे के प्रति अधिक खुली हैं।

तथापि, अन्वियों की तुलना में जबकि राष्ट्रीय जीडीपी का आकार काफी महत्वपूर्ण है, क्रय शक्ति समता के अनुसार प्रत्येक देश में प्रति व्यक्ति जीडीपी का स्तर भी कुछ संबद्ध है। मेडिसन के अनुमानों के अनुसार, चीन की प्रति व्यक्ति जीडीपी वर्ष 2030 में अमरीकी की लगभग एक चौथाई होगी, यद्यपि चीन की जीडीपी के अगले पचीस वर्षों के भीतर अमरीका से आगे निकल जाने की आशा है। इससे व्यापक रूप से उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में अधिकांश एशियन अर्थव्यवस्थाओं की स्थिति परिलक्षित होती है। संक्षेप

में, इसलिए, विनम्रता के पुट के साथ उदीयमान एशिया के प्रति समुचित उत्साह दिखलाना एक अच्छी बात है, जिसकी आवश्यकता आगे पड़ी लंबी यात्रा में आएगी।

एशिया की प्रभावकारी वृद्धि ने अनेक तरीकों से वैश्विक अर्थव्यवस्था को लाभ पहुँचाया है, यद्यपि कुछ मुद्दे उभर कर सामने आए हैं। प्रथम, अत्यधिक प्रतियोगी माल और सेवाओं का उत्पादन करके, एशिया में उपलब्ध माल के रेंज को बढ़ाने में मदद मिली है और उनकी गुणवत्ता बढ़ी है। परिणामस्वरूप, विश्वभर में एक समूह के रूप में बिलियन उपभोक्ता एशिया में वृद्धि से लाभान्वित हुए हैं। इस प्रक्रिया ने केंद्रीय बैंकों को, वैश्विक रूप से मुद्रास्फीति और मुद्रास्फीतिकारी प्रत्याशाओं को रोकने में मदद की है। एशिया में उपलब्ध श्रमशक्ति की विशाल संख्या जो आगामी कई दशकों तक रहेगी, और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुई प्रगति को देखते हुए कइयों को प्रक्रिया के जारी रहने की आशा है, शायद अनिवार्य रूप से उसी गति के साथ नहीं।

दूसरे, कई पण्य उत्पादक देश, विशेष रूप से अफ्रीका और लैटिन अमरीका में, व्यापार की बेहतर शर्तों और निर्यात की बढ़ी हुई आय तथा बढ़ी हुई आर्थिक गतिवधि के माध्यम से एशिया की बढ़ रही मांग को पूरा करके, लाभान्वित हुए हैं। इस प्रकार, एशिया वैश्विक वृद्धि के लिए जोर देकर अमरीका का संपूरक बना। चूँकि एशिया में वृद्धि की गति के जारी रहने की आशा है, सकारात्मक प्रभाव के जारी रहने की आशा है।

तीसरे, एशिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में तीव्र वृद्धि से अन्य अर्थव्यवस्थाओं, विशेष रूप से पड़ोसी अर्थव्यवस्थाओं के बाजारों को बढ़ाने के पर्याप्त अवसर उत्पन्न होना जारी रहेंगे और इसमें निश्चित रूप से पर्यटन और वित्तीय उत्पाद भी शामिल होंगे।

चौथे, एशिया के उदय से कतिपय उन्नत अर्थव्यवस्थाओं को कुछ असुविधा का अनुभव हुआ क्योंकि प्रतिस्पर्धी शक्तियों ने कामगारों के कुछ वर्गों की मजदूरी पर प्रभाव डाला है, यद्यपि उपभोक्ता के रूप में सामान्य जनता इस प्रक्रिया से लाभान्वित हुई।

पाँचवें, तीव्र गति से बढ़ते एशिया के कारण ऊर्जा की मांग बढ़ी है और कुछ लोगों के अनुसार, इससे तेल के मूल्यों पर प्रभाव पड़ा है। ऊर्जा की खपत के वर्तमान स्तर के अनुसार, एशिया अभी भी समग्र ऊर्जा बाजार में एक छोटा सहभागी है और कई लोग पण्यों और सट्टा के वित्तपोषण के लिए तेल के बढ़ते मूल्यों को कारण मानते हैं। निसंदेह, मध्यम से दीर्घावधि में, एशिया में ऊर्जा के प्रयोग में क्षमता बढ़ाने की गुंजाइश है। विश्व की ईंधन अर्थव्यवस्था और एशिया का उदय भविष्य में भी गत्यात्मक तरीके से अंतःक्रिया करते रहेंगे।

छठे, एशिया में तीव्र वृद्धि से अप्रत्याशित संख्या, मिलियन में लोग प्रतिवर्ष निर्धनता के स्तर से ऊपर उठ रहे हैं, इस प्रकार अनाज और दूध सहित खाद्य वस्तुओं की मांग उत्पन्न रही है। एशिया के कारण खाद्य की मांग में संरचनात्मक वृद्धि कई वर्षों तक जारी रहेगी। जबकि खाद्य की मांग सापेक्षिक रूप से लोचहीन है, पूर्तिपक्ष प्रायः राजनैतिक अर्थव्यवस्था के विचार के साथ-साथ अनेक कारकों से प्रभावित होता है। यह समस्या वैश्विक वातावरण दशाओं की अनिश्चितता और इन पण्यों में व्यापार के बढ़ रहे वित्तपोषण से बढ़ती है।

अंत में, मौद्रिक प्राधिकारी बड़ी जटिल चुनौतियों का सामना कर रहे हैं क्योंकि पारंपरिक तौर पर तेल के मूल्यों को 'आघात' माना जाता था और खाद्य के मूल्यों को भी एक प्रकार का 'आघात' माना जाता है। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में भी अब मौद्रिक प्राधिकारियों द्वारा

महसूस किया गया है कि खाद्य मूल्यों का मुद्रास्फीतिक प्रत्याशाओं पर काफी प्रभाव पड़ता है, जो मौद्रिक नीति के संचालन के लिए आवश्यक है। विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में समस्या और गंभीर है क्योंकि मूल्य सूचकांक में खाद्य मूल्यों का भार अधिक है।

भविष्य में, हम सब एक परस्पर निर्भर विश्व में एशिया के बढ़ते महत्व को स्वीकार करते हैं। इसलिए, एशिया को सार्वजनिक नीति की चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है और अंतरराष्ट्रीय समुदाय को उन नीतियों के प्रति अनुकूल होने से लाभ मिलेगा जो मध्यम अवधि से दीर्घ अवधि में एशिया और वैश्विक अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचाएंगी। ऐसी सहयोगी और आपस में सुदृढ़ करने वाली नीतियां सभी क्षेत्रों में वृद्धि और स्थायित्व के लिए महत्वपूर्ण हैं।

अब मैं एशिया में कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियों के बारे में बताऊंगा। एक, एशिया में विश्व के दो-तिहाई लोग घोर गरीबी में रहते हैं। एशियाई विकास बैंक के अनुसार क्षेत्र के भीतर 620 मिलियन लोग अभी भी एक अमरीकी डॉलर प्रति दिन से कम में जीवन-यापन करते हैं और यदि हम प्रति दिन दो अमरीकी डॉलर की सीमा बढ़ाते हैं, तो यह संख्या एक बिलियन से अधिक होगी। इसलिए, समग्र वृद्धि की नीति महत्वपूर्ण और वास्तव में आवश्यक हो जाती है।

दूसरे, अन्य क्षेत्रों के सापेक्ष में, एशिया में अरबपतियों और बड़ी हैसियत वाले व्यक्तियों का हिस्सा विषमतापूर्वक बढ़ रहा है, जिससे सामाजिक और राजनैतिक स्थायित्व को बनाए रखने संबंधी चिंताएं प्रकट हो सकती हैं। बढ़ती क्षेत्रीय असमानताओं के दुष्परिणामों को एशिया की कई अर्थव्यवस्थाओं में महसूस

किया जा रहा है। इस संबंध में अनेक नीतिगत कदम भी उठाए गए हैं।

तीसरे, वर्ष 2000 के सापेक्ष में, वर्ष 2030 तक एशिया में शहरी आबादी दोगुनी हो सकती है। 2030 तक, एशिया में शहरी लोग लगभग 2.7 बिलियन होंगे, जबकि विश्व के अन्य सभी क्षेत्रों की संयुक्त शहरी आबादी लगभग 2.3 बिलियन होगी। इससे शहरी इन्फ्रास्ट्रक्चर की व्यापक मांग होगी। इसी तरह, वैश्वीकरण और वृद्धि के अनुभवों के कारण शहरी निवासी शहरी इन्फ्रास्ट्रक्चर और सेवाओं की गुणवत्ता की अधिक मांग करेंगे। इसलिए, राष्ट्रीय सीमाओं के बाहर सार्वजनिक-निजी सहभागिता महत्वपूर्ण हो सकती है।

चौथे, अगले 50 वर्षों में एशिया की जनांकिकीय प्रवृत्तियों में विकसित देशों के विगत 50 वर्ष परिलक्षित होने की आशा है जिसमें एशिया की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं के बीच काफी विषमता है। 2000 से 2025 के दौरान और आगे 2050 तक वृद्धावस्था निर्भरता में प्रत्याशित वृद्धि राजकोषीय दबावों को बढ़ा सकती है। भारत और इंडोनेशिया जैसे देश, अन्य एशियाई अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में, लंबी अवधि तक, शायद दूसरे 25 वर्षों तक, जनांकिकीय लाभांश का फायदा उठाते रहेंगे। जनांकिकीय लाभांश के फायदे स्वास्थ्य दशाओं की गुणवत्ता बढ़ाने, बेहतर कार्य कुशलता प्रदान करने और सार्वजनिक आधारभूत सुविधाओं में सुधार करने पर निर्भर है जिससे वैश्वीकरण का लाभ उठाया जा सके। समुचित सार्वजनिक नीतिगत पहलों के अभाव में जनांकिकीय लाभांश जनांकिकीय समस्या में बदल सकते हैं।

अंत में, वैश्विक समुदाय को वर्तमान अंतरराष्ट्रीय वित्तीय ढाँचे में उदीयमान एशिया के प्रति आवाज और

प्रतिनिधित्व की पर्याप्तता के मुद्दे को उठाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, अभिशासन ढाँचे और व्यवस्था को सभी दावेदारों के हित में तेजी से विकासमान एशिया की नई वास्तविकताओं को ध्यान में रखने की आवश्यकता है।

सामायिक महत्व का एक मुद्दा वैश्विक वित्तीय बाजार और एशिया में वर्तमान घटनाओं के बीच अंतः क्रिया है। वित्तीय बाजार और संस्थाओं के सभी संबंधित पहलुओं को अभी पूरी तरह से पारदर्शी करना है। ऐसा महसूस किया जा रहा है कि वैश्विक वित्तीय बाजारों में पूरी सामान्यता अभी बहाल की जाती है। संयुक्त राज्य अमरीका में वास्तविक अर्थव्यवस्था पर प्रभाव को अभी पूरी तरह से महसूस किया जाना है और उस अर्थव्यवस्था में मंदी से इनकार नहीं किया जा सकता है। जबकि अमरीकी अर्थव्यवस्था में न तो वित्तीय छुआछूत और न ही मंदी से इनकार किया जा सकता है, अब तक वैश्विक सहमति है कि वैश्विक वृद्धि प्रत्याशा के अनुसार सुदृढ़ होगी लेकिन बहुत अधिक अनिश्चितताओं के साथ। इस चरण में, इसलिए, एशिया पर वैश्विक वित्तीय दशाओं के संभावित प्रभाव संबंधी केवल थोड़े से व्यापक विचार व्यक्त किए जा सकते हैं।

वास्तविक क्षेत्र में आर्थिक सुधारों ने एशिया में समग्र उत्पादकता और नमनीयता में सुधार किया है। एशिया में समष्टि आर्थिक दशाएं, कुल मिलाकर, काफी सुदृढ़ और विगत से संबंधित समग्र स्थायित्व के लिए सहायक हैं। अधिकांश देशों के बाजारों और संस्थाओं की वित्तीय प्रणालियां, पहले की अपेक्षा काफी अधिक कारगर और नमनीय हैं। बाह्य क्षेत्र सुदृढ़ हुआ है और वित्तीय संक्रमण का सामना करने के लिए 'कुशन' प्रदान करने हेतु पर्याप्त भंडार हैं। वास्तव में, ऐसा बहुतों द्वारा महसूस किया गया है कि एशिया के भंडार वैश्विक असंतुलनों को दूर

करने की प्रक्रिया को सुकर बनाने में मदद कर सकते हैं, जो जारी प्रतीत होती है और जिसे “पैराशूट के साथ गिरने” के परिदृश्य के रूप में वर्णित किया जा सकता है। समग्रतः, एशिया की अर्थव्यवस्थाएं अधिकांश वित्तीय बाजारों की अत्यधिक अस्थिरता का कुछ सीमा तक, सामना करने के लिए समुचित रूप से सुसज्जित हैं।

तथापि, वास्तविक क्षेत्र में प्रतिकूल परिस्थितियों का, यदि वे होती हैं, संभावित प्रभाव कम स्पष्ट हैं। जबकि कुछ का कहना है कि अमरीका की मंदी का एशिया पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, चूँकि अमरीका को एशिया का निर्यात काफी अधिक है, दूसरों का कहना है कि बढ़ रहे आंतर-एशिया क्षेत्रीय व्यापार की दृष्टि से कुछ “डी-कपलिंग” की स्थिति प्रकट हुई है। यह भी तर्क दिया गया है कि एशिया का आंतर-क्षेत्रीय व्यापार अमरीका को किए गए निर्यात से संबद्ध है। एक और विश्वसनीय बात होगी कि यदि अमरीका में मंदी होती है तो, कुछ सीमा तक, एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में वृद्धि को कम करेगी, लेकिन जिस सीमा तक डिकपलिंग का कुछ तत्व होगा, जो देश विशिष्ट भी होगा, प्रभाव कम होगा। दूसरे शब्दों में, यह कहना अवास्तविक होगा कि इस अवस्था में एशिया वैश्विक वृद्धि के प्रमुख इंजन के रूप में अमरीका को प्रतिस्थापित कर सकता है। इसलिए एशिया के केंद्रीय बैंकों के बीच अत्यधिक सतर्कता सामान्य प्रतीत होती है।

हम, भारत में (क) वैश्विक वित्तीय बाजार में पूर्ण सामान्यता की पुनर्स्थापना के लिए प्रक्रिया; (ख) उभरते वित्तीय संक्रमण; और (ग) ‘डि कपलिंग’ की संभावित सीमा के लिए गणना करने के पश्चात वास्तविक क्षेत्र के प्रति संभावित प्रकीर्णन की निगरानी कर रहे हैं। इस समय भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा असाधारण सतर्कता

का मुख्य कारण, वैश्विक रूप से कई महत्वपूर्ण बाजारों अर्थात्, मुद्रा, ऋण और करेंसी बाजार, आस्ति मूल्य तथा पण्य मूल्य, विशेष रूप से तेल और खाद्य वस्तुओं, में समकालीन अस्थिरता है। समकालीन अस्थिरता के वर्तमान परिदृश्य को विश्व के प्रबल मुद्रा भंडारों के संभावित पुनर्व्यवस्थापन के संदर्भ में देखा जाना चाहिए जिसमें पर्याप्त संपदा, आय और व्यापार प्रभाव शामिल हैं।

देवियों और सज्जनो, अब मैं भारतीय अर्थव्यवस्था पर विस्तार से प्रकाश डालूंगा। स्वतंत्रता के पहले, 20वीं शताब्दी के पहले पाँच दशकों के दौरान (1900-01 से 1946-47 तक), भारतीय अर्थव्यवस्था का वार्षिक औसत वृद्धि प्रदर्शन बहुत धीमा था, जिसका औसत प्रति वर्ष 0.9 प्रतिशत था। 1950 के दशक के प्रारंभ में, नियोजित विकास प्रक्रिया की शुरुआत से, जीडीपी वृद्धि में स्व-प्रेरक प्रवृत्ति दिखी, जो 1990 के दशक में लगभग 6.0 प्रतिशत पर पहुंच गई। इस चरण के दो अपवाद थे - 1970 के दशक में वृद्धि दर का 2.9 प्रतिशत तक गिरना और 1991-92¹ का संकट वर्ष जब वृद्धि 1.4 प्रतिशत की निचाई पर थी।

नई सहस्राब्दी में, 2000-01 से 2006-07 तक के सात वर्षों के दौरान जीडीपी की वृद्धि दर और बढ़ी है जिससे औसत 6.9 प्रतिशत हो गया है, जबकि पिछले चार वर्षों (2003-04 से 2006-07 तक) में वृद्धि दर का औसत 8.6 प्रतिशत था। 2005-06 और 2006-07 में यह और बढ़कर क्रमशः 9.0 प्रतिशत और 9.4 प्रतिशत हो गया है। इस चरण के दौरान भी, 2002-03 के दौरान एक वर्ष में, देश के अनेक हिस्सों में सूखे की स्थिति के कारण, जिससे कृषि उत्पादन में काफी गिरावट हुई, वृद्धि दर घटकर 3.8 प्रतिशत हो गई।

हाल के वर्षों में आर्थिक गतिविधि की सुदृढ़ता को सकल घरेलू निवेश दर में 2000-01 में जीडीपी के 24.3 प्रतिशत से 2005-06 में 33.8 प्रतिशत और

1. भारत में राजकोषीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च।

घरेलू बचत दर में 2000-01 में 23.7 प्रतिशत से 2005-06 के दौरान 32.4 प्रतिशत की लगातार वृद्धि से समर्थन मिला है। यह महत्वपूर्ण बात है कि इस अवधि के दौरान निवेश के 90 प्रतिशत से अधिक को घरेलू बचतों से वित्तपोषण मिला।

अर्थव्यवस्था में निवेश की दर में वृद्धि के अनुरूप, उत्पादता में और पूँजी के प्रयोग की कुशलता में तेजी के प्रमाण हैं। भारत से संबंधित हाल के कुछ अध्ययनों में हाल के वर्षों में कुल कारक उत्पादकता में वृद्धि के संकेत हैं।

जबकि नई सहस्राब्दि में वृद्धि दर बढ़ी है, मुद्रास्फीति की दर में अभी थोड़ी सी कमी आई है जिससे मूल्य स्थिरता सुनिश्चित हुई है। 2000-01 से, थोक मूल्य सूचकांक के मापन के अनुसार, वार्षिक मुद्रास्फीति दर का औसत हाल के तेल मूल्यों के आघात के बावजूद 5 प्रतिशत से नीचे है।

केंद्र और राज्यों के संयुक्त राजकोषीय घाटे के 2000-01 में जीडीपी के 9.5 प्रतिशत से कम होकर 2006-07 में 6.4 प्रतिशत रह जाने के कारण देश के राजकोषीय प्रबंधन में काफी सुधार हुआ है। तथापि, केंद्र और राज्यों का संयुक्त सार्वजनिक ऋण, जीडीपी के प्रतिशत के रूप में, 70 प्रतिशत पर अधिक बना हुआ है।

2001-02 से 2003-04 के दौरान कई वर्षों के मामूली अधिशेष के पश्चात, चालू खाता घाटा बहुत कम स्तर पर बनाए रखने के कारण भारत का बाह्य क्षेत्र लोचपूर्ण हो गया है। निर्यात और आयात दोनों का मूल्य, अमरीकी डालर में, 2000-01 के सापेक्षिक 2006-07 में तीन गुना हो गया है और चालू खाता घाटा सात वर्षों में से चार वर्ष के लिए, जीडीपी के 1.1 प्रतिशत पर कम बना रहा, जबकि बाद के वर्षों में अधिशेष की स्थिति

थी। सुदृढ़ पूँजी प्रवाहों के कारण विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि हुई है जो 16 नवंबर 2007 को 271.2 बिलियन अमरीकी डालर था तथा वर्तमान में बाह्य ऋण (जून 2007 के अंत में 165.4 बिलियन अमरीकी डालर) की तुलना में अधिक है।

ऐसा मानते हुए कि कच्चे तेल के अंतरराष्ट्रीय मूल्यों में कोई वृद्धि नहीं होगी और घरेलू अथवा बाह्य आघातों का सामना नहीं करना पड़ेगा, मौद्रिक नीति प्रयोजनों के लिए, रिजर्व बैंक ने अप्रैल 2007 के अपने वार्षिक नीति वक्तव्य में वर्तमान वर्ष 2007-08 की वास्तविक जीडीपी वृद्धि 8.5 प्रतिशत रखी।

आगे की अवधि के लिए नीतिगत अधिमान्यता प्रबल रूप से मूल्य स्थिरता और सुस्थिर मुद्रास्फीतिक प्रत्याशाओं के पक्ष में है जिसमें 2007-08 में मुद्रास्फीति को 5.0 प्रतिशत के करीब लाने का प्रयास किया जाएगा। इस संबंध में, वैश्विक अर्थव्यवस्था और सामाजिक अधिमान्यताओं के साथ भारत के बढ़ते समन्वयन को स्वीकारते हुए, आगे संकल्प होगा कि प्रत्याशाओं को 4.0-4.5 प्रतिशत की सीमा में रखा जाए जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत के व्यापक समन्वयन के अनुरूप 3.0 प्रतिशत की मुद्रास्फीति दर मध्यम कालिक उद्देश्य बन जाए।

मध्यम काल में भारतीय अर्थव्यवस्था को कुछ प्रमुख चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। प्रथम, भारतीय जनसंख्या का लगभग 60 प्रतिशत अभी भी कृषि पर निर्भर है, जीडीपी में इसका हिस्सा वर्षों से लगातार गिर रहा है और अब जीडीपी के 20 प्रतिशत से कम है। इसलिए, कृषि क्षेत्र में अधिक वृद्धि खाद्य सुरक्षा, निर्धनता उन्मूलन, मूल्य स्थिरता, अर्थव्यवस्था की समग्र

सम्मिलित वृद्धि और धारणीय वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। दूसरे, आधुनिक आधारभूत सुविधाओं का अभाव और कुशल मानवशक्ति की कमी वृद्धि के लिए सर्वाधिक प्रमुख बाधाएं हैं। इसलिए, उद्योग की समृद्धि के लिए सशक्त वातावरण बनाने हेतु वर्तमान आधारभूत सुविधाओं, विशेष रूप से रोड, बंदरगाह और विद्युत को और बढ़ाने की आवश्यकता है। तीसरे, जनांकिकीय लाभांशों का फायदा उठाने के लिए शिक्षा क्षेत्र में वास्तविक प्रसार और सुधारों की तुरंत आवश्यकता होगी। चौथे, सरकार की परिचालनात्मक कार्यक्षमता को रोके बिना राजकोषीय अनुशासन को बढ़ाने के लिए उच्च पूंजी परिव्यय के साथ सामाजिक क्षेत्र के प्रति व्ययों का पुनः प्राथमिकीकरण आवश्यक है। राजकोषीय सशक्तीकरण उच्च पूंजी परिव्यय की अनुमति देगा और आधारभूत सुविधाओं और सामाजिक क्षेत्र के व्यय को बढ़ावा देगा जिसका घरेलू उत्पादकता, वृद्धि और रोजगार पर लाभपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार, यह जरूरी है कि राजकोषीय समायोजन की गुणवत्ता के महत्त्व पर बल दिया जाए। अंत में, ऋण की बढ़ती मांग को पूरा करने और उच्च आर्थिक वृद्धि को बनाए रखने के लिए बैंकों को अपने जमा आधार को बढ़ाने की आवश्यकता है। बैंकों को अधिक से अधिक वित्तीय रूप से वंचित वर्ग को अपनी सुविधा क्षेत्र के अंतर्गत लेने की आवश्यकता है जिससे कम-आय के परिवारों की मदद होगी और वित्तीय गहनता सुदृढ़ होगी।

मैंने कुछ देर पहले ही भारतीय अर्थव्यवस्था के कुछ संख्यात्मक सकारात्मक पहलुओं की चर्चा की है जैसे बचत-निवेश शेष, और मूल्य स्थायित्व। अब, मैं कुछ गैर-संख्यात्मक प्रमुख ताकतों की बात करूंगा जिनसे ऊपर उल्लिखित चुनौतियों का सामना करने में मदद मिलने की आशा है। पहले, इसके पास विज्ञान और

प्रौद्योगिकी स्नातकों की बहुत बड़ी संख्या है और दसियों लाख ऐसे लोग हैं तो अंग्रेजी भाषा जानते हैं। दूसरे, अनेक भाषाओं की जानकारी बहु सांस्कृतिक स्थितियों का अनुकूलन बेहतर बना देती है जिससे अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में आसानी से खपने के लिए भारतीय मानवशक्ति को सुविधा होती है। तीसरे, संसार का सबसे बड़ा प्रजातंत्र तथा मुक्त प्रेस का अस्तित्व ज्यादतियों के विरुद्ध कुछ सुरक्षा प्रदान करता है तथा सरकारों को पहले की अपेक्षा और अधिक उत्तरदायी बनाता है। चौथे, हाल के वर्षों में महिला सशक्तीकरण से उन्हें अपने अधिकारों की रक्षा करने में मदद मिली है तथा और अधिक आत्मसम्मान बनाने और उन्हें अपने वैयक्तिक जीवन तथा सामाजिक संबंधों पर नियंत्रण स्थापित करने में सहायता मिली है। पांचवें, मिले-जुले मंत्रिमंडलों और आवधिक चुनावों के बावजूद, राजनैतिक वातावरण में राजनैतिक प्रणाली की स्थिरता बनी हुई है। छठवें, कुशलता, अद्यतनीकरण और सुदृढ़ अभिशासन जैसी पूर्वपिक्षाओं के द्वारा पर्याप्त "जनांकिकीय लाभांश" प्राप्त किया जा सकता है। अंत में, कारोबार वातावरण में, एक तेजी से उभरता बहुत बड़ा उद्यमी वर्ग, जो नवोन्मेषण का इच्छुक और पेशेवर वाद से परिपूर्ण है, वैश्विक तौर पर प्रतियोगी होना चाह रहा है।

तथापि, अर्थव्यवस्था का लगातार सफलतापूर्वक निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए, यह सामान्य रूप से माना जाता है कि सभी हितधारकों को राज्य की क्षमता को मजबूत करने की आवश्यकता है और इसको, इसके मूल कार्यों को और प्रभावपूर्ण तरीके से और समानता से करने के लिए, समर्थ बनाना है।

सामान्य रूप में, उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं और विशेष रूप में, भारत के लिए दीर्घकालिक आर्थिक

दृष्टिकोण का उल्लेख करते हुए यूरोपियन सेंट्रल बैंक के अध्यक्ष, श्री जीन-क्लाउड ट्रिशे ने 26 नवंबर 2007 को दसवें एल.के.झा स्मारक भाषण में कहा कि "यह स्मरण करना पर्याप्त होगा कि दो सहस्राब्दियों के पहले विश्व अर्थव्यवस्था में भारत का वजन कितना अधिक था, जब मध्य काल के राजा भारत में राज्य करते थे और रोमन साम्राज्य यूरोप और उत्तरी अफ्रीका में शासन कर रहा था। उस समय, भारत विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति थी, जिसका विश्व उत्पादन में अकेले हिस्सा लगभग एक तिहाई था। तो भी, चीन के बराबर, औद्योगिक क्रांति के पहले तक, कई शताब्दियों तक विश्व में यह सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहा। ऐसी लंबी पृष्ठभूमि को देखते हुए, आज की विश्व अर्थव्यवस्था में भारत की तेजी से बढ़ती महत्ता से प्रतीत होता है कि यह सामान्य स्थिति की ओर प्रस्थान कर रहा है"।

निष्कर्षात्मक टिप्पणी

गवर्नर भीनिक ने कुछ सप्ताह पहले केपटाउन में आयोजित अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक/अफ्रीकन गवर्नरों के सम्मेलन के अवसर पर एक प्रस्तुति में मारीशस की उपलब्धियों, नीतियों और चुनौतियों का एक बुद्धिमत्तापूर्ण चित्रण प्रस्तुत किया था। इसलिए, मैं, उनके नेतृत्व में मारीशस और विशेष रूप से, बैंक ऑफ मारीशस के उज्ज्वल भविष्य के प्रति आश्वस्त हूँ। मारीशस की अर्थव्यवस्था और मारीशस की जन नीति के कुछ उदाहरणयोग्य पहलू हैं जो अन्य देशों के लिए

अनुकरणीय हैं, विशेष रूप से भारत सहित एशिया की अर्थव्यवस्थाओं के लिए, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। अब मैं इनमें से कुछ पहलुओं की चर्चा करूँगा जिनका हमें एशिया में अनुकरण करने और आत्मसात करने की सलाह दी जाएगी।

"अफ्रीकन बिजनेस" के नवंबर 2007 के अंक में अफ्रीकन अभिशासन 2007 पर एक सूचकांक छपा है और अंतिम गणना के अनुसार, मारीशस अफ्रीका में पहले स्थान पर है। विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम के ताजा वैश्विक अफ्रीकन प्रतिस्पर्धी सूचकांक में भी मारीशस का पहला स्थान है। मेरा व्यक्तिगत विचार है कि एशिया में, हममें से बहुत से देश प्राथमिक शिक्षा की व्याप्ति और गुणवत्ता, स्वास्थ्य सेवाओं की प्रभावी प्रदायगी तथा वातावरण की सुरक्षा से संबंधित मारीशस की जन नीतियों का अध्ययन कर सकते हैं और सीख ले सकते हैं। हाँ, हम एक दूसरे से बहुत कुछ सीख सकते हैं और ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं, जहाँ हम सहयोग कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि दोनों केन्द्रीय बैंक पारंपरिक संबंधों को मजबूत बनाएंगे। हम बैंक ऑफ मारीशस और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच सहयोग को मजबूत करने के लिए निरंतर चर्चा कर सकते हैं।

आपसी सद्भाव के रूप में, मैं गवर्नर श्री भीनिक को भारत का दौरा करने और इसके अलावा, रिजर्व बैंक के 75 वें वार्षिक समारोह में, जो अबसे कुछ ही वर्षों में आयोजित किया जाने वाला है, भाग लेने के लिए खुले हृदय से आमंत्रित करता हूँ।